

देश की उपराज्य

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03

अंक - 46

जौनपुर, गुरुवार, 03 अक्टूबर 2024

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें

तीसरे और आखिरी चरण के साथ ही जम्मू-कश्मीर में खत्म हुआ मतदान का दौर

जम्मू-कश्मीर, एजेसी। तीसरे और आखिरी चरण के मतदान के साथ ही जम्मू-कश्मीर में वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। जम्मू-कश्मीर चुनाव के नतीजे आठ अक्टूबर को आएंगे। तीसरे एवं अंतिम चरण के तहत मंगलवार को शाम पांच बजे तक 65.48 प्रतिशत मतदान हुआ। उधमपुर जिले में सबसे अधिक 72.91 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद सांबा (72.41 प्रतिशत), कठुआ (70.53 प्रतिशत), जम्मू (66.79 प्रतिशत), बांदीपुरा (63.33 प्रतिशत), कुपवाड़ा (62.76 प्रतिशत) और बारामूला (55.73 प्रतिशत) का स्थान रहा। अधिकारियों ने बताया कि सभी क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चला और कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। चुनाव के इस चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में रमन भल्ला (आरएस पुरा), उस्मान माजिद (बांदीपुरा), नजीर अहमद खान (गुरज), तज मोहिउद्दीन (उरी), बशाहत बुखारी (वाग्रा-झरी), इमरान अंसारी (पट्टन), गुलाम हसन मीर (गुलमर्ग), चौधरी लाल सिंह (गुलमर्ग), राजीव जसरोटिया (जसरोटा), मनोहर लाल शर्मा (बिलावर), श्याम लाल शर्मा और अजय कुमार सधोत्रा (जम्मू उत्तर) शामिल हैं।

आठ अक्टूबर के बाद आईसीयू में नजर आएगी कांग्रेस - सीएम नायब सिंह सैनी

हरियाणा, एजेसी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा प्रत्याशी डॉ. कृष्ण मिश्रा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आठ अक्टूबर के बाद कांग्रेस आईसीयू में नजर आएगी। इस बार भाजपा जीत का परचम लहराने जा रही है। सीएम सैनी ने कहा, "चुनावी प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर है। भाजपा का चुनाव ऊंचाइयों पर है, जबकि कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती जा रही है। सूबे की जनता ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया है।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस अब हरियाणा की राजनीति से गायब हो जाएगी। कांग्रेस ने इस बार दो बार अपना मेनिफेस्टो जारी किया, लेकिन जनता ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी, जिससे उसकी हवा निकल गई। गांधी और प्रियंका गांधी के हरियाणा दौरों को लेकर भी कटाक्ष किया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हरियाणा की राजनीति में पर्यटन के लिए आ रहे हैं। आप यहां घूमने के लिए आ रहे हैं, हम पिछले 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं।

सीएम योगी ने पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया



लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैरा-2024 में संपन्न ओलंपिक एवं पैरालंपिक गेम्स में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये के चेक वितरित

किए। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियां भी इंजंजाम कर रही हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आम जीवन में खेलों के महत्व को नाकारा नहीं जा सकता। इससे तन और मन दोनों ही स्वस्थ

रहता है। इसलिए हमें खेलों को अनिवार्य रूप से अपनाया चाहिए। स्मार्टफोन और नशे से जितना दूर रहेंगे, भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा। समारोह में सम्मानित होने वाले 14 खिलाड़ियों के बीच 22 करोड़ 70 लाख की कुल धनराशि वितरित की गई। जबकि चार प्रशिक्षकों को 29 लाख रुपये दिए गए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक जैसे बड़े खेल मंच पर दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पैरा खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों को पीछे

छोड़ दिया। इस प्रदर्शन में प्रवीण कुमार, सुहास एलवाई और अजीत सिंह का प्रदर्शन काबिले-तारीफ रहा। सामान्य खिलाड़ियों में ललित ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया, जबकि गाजीपुर जैसे छोटे जिले से निकलकर राजकुमार पाल ने भारतीय हॉकी टीम से ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर अपना लोहा मनवाया। इन सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से राजपत्रित अधिकारी बनाया जाएगा। इसके अलावा हमने खिलाड़ियों के साथ उनके प्रशिक्षकों को भी प्रोत्साहन राशि दी है। योगी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं और सीएम मोदी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास किए

जा रहे हैं। यहां जनपद स्तर पर कम से कम एक स्टेडियम और ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक ओपन जिम प्रावधान किया गया है, ताकि प्रत्येक क्षेत्र की प्रतिभाएं निखकर सामने आए। इसके अलावा खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई। प्रदेश में खिलाड़ियों की संख्या में इजाफा भी हुआ, जो प्रदेश के सुखद खेल भविष्य का परिचायक है। समारोह के दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र शाही और खेलमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने पैरा-ओलंपिक में पदक विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए भविष्य की शुभकामनाएं दी।

स्थिति स्थिर, लेकिन तनावपूर्ण, - सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी

नई दिल्ली, एजेसी। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने मंगलवार को उत्तर में शांति बहाल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि मणिपुर संघर्ष समय के साथ कहानियों की लड़ाई बन गया है और हिंसाग्रस्त राज्य में स्थिति भले ही स्थिर हो, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। चाणक्य रक्षा संवाद, 2024 में बोलते हुए जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने कहा कि हल्के-फुल्के अंदाज में कहें तो शक के साथ एक आजाद क्योंकि मणिपुर एक समस्या थी और अब आपके सामने म्यांमार की समस्या भी आ रही है। लेकिन तनावपूर्ण है। सबसे पहले, हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यह संपूर्ण राष्ट्र का दृष्टिकोण होना चाहिए। हम विश्वास बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बड़ी संख्या में हथियार बरामद करने में सफल रहे हैं। जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने आगे कहा कि अगर मैं कहता हूं कि लगभग 25% हथियार पहले ही बरामद किए जा चुके हैं और स्थानीय किस्म के दोगुने हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं। हमें झूठी कहानियों की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, बम ड्रॉन की कहानी थी। हमने जमीन पर जाकर जांच की और वहां कोई बम ड्रॉन नहीं थे।

मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपने देश को विकसित बनाएंगे, किसान संगठनों से मिले शिवराज चौहान

हरियाणा, एजेसी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार अलग-अलग किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को उन्होंने भारतीय किसान यूनियन (स्वतंत्र) संगठन के लोगों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान शिवराज ने कहा कि किसानों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान करने से उनकी आय 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। आपको बता दें कि शिवराज ने 24 सितंबर को किसानों से बातचीत के लिए सीधी संवाद शुरू किया था। हमने तय किया था कि हर मंगलवार किसान संगठनों के मित्रों और किसान प्रतिनिधियों से मिलकर संवाद करेंगे। इसी क्रम में आज भारतीय किसान यूनियन (स्वतंत्र) संगठन के साथियों से भेंट हुई और कई महत्वपूर्ण विषयों



पर उनसे चर्चा की। उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, जिस पर हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर कृषि की लागत को कम करने, खेती को लाभकारी बनाने सहित विविध विषयों पर चर्चा हुई और साथ ही कई सुझाव भी आए। पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लिए विकसित खेती के

संकल्प की सिद्धि में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मिलकर आगे बढ़ेंगे और अपने देश को विकसित बनाएंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने कारखाने के दूषित पानी और जले हुए ट्रांसफार्मर को कम समय में बदलने पर चर्चा की।

देश की एकता तोड़ने के लिए नए-नए प्रयोग कर रही कांग्रेस - मोदी

हरियाणा, एजेसी। हरियाणा के पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी सभा करने पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री और भाजपा नेता नायब सिंह सैनी और अन्य पार्टी नेताओं ने उनका अभिनंदन किया। अपने संबोधन के शुरुआत में मोदी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा को भारी बहुमत से जिताने का निश्चय कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक हरियाणा की जमीनी राजनीति को देखा है। बीते दिनों हरियाणा के अलग-अलग क्षेत्र में मुझे चुनाव अभियान के लिए, जनता-जनार्दन के दर्शन के लिए जाने का अवसर मिला है। आज इस चुनाव की ये मेरी अंतिम सभा है। आपने भी मेरी इस चुनाव की आखिरी सभा को

चार चांद लगा दिए हैं। मोदी ने कहा कि आज गांव-गांव में चारों तरफ भाजपा की लहर है। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है - भरोसा दिल से, भाजपा फिर से...। उन्होंने कहा कि हरियाणा का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती है, हरियाणा में भी उसी की सरकार बनती है। आपने दिल्ली में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई, अब यहां हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा सरकार बनाना आप लोगों ने तय कर लिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हमें सिखाया है कि काम करो, मेहनत से करो। कांग्रेस का फॉर्मूला है- ना काम करो और ना दूसरों को काम करने दो। कांग्रेस की राजनीति केवल झूठे वादों तक सीमित रहती है, जबकि भाजपा की राजनीति मेहनत और परिणामों पर टिकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम



परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि कांग्रेस कभी भी खुद मेहनत नहीं करती। कांग्रेस को लगता था कि 10 साल हो गए, हरियाणा वाले उन्हें थाली में परोसकर सत्ता दे देंगे, यही गलतफहमी कांग्रेस को म् सीमित रहती है, जबकि भाजपा की राजनीति मेहनत और परिणामों पर टिकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम

जनता ने वोटिंग के दिन कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए। उन्होंने कहा कि यही हरियाणा में कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है, उसे भी यहां के लोग देख रहे हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े, वंचित समाज की है। दलित य प्रदेश में भी थी, वहां भी कांग्रेस के लोग पहले ही जीत का जश्न मनाने लगे थे। लेकिन मध्य प्रदेश की

कांग्रेस में कल्पयुजन ही कल्पयुजन - भूपेंद्र चौधरी

लखनऊ, संवाददाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सोमवार को कांग्रेस पर

में एक ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम योगी पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप

लोग नेगेटिव एजेंडा फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, वह प्रशंसनीय है।



जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कल्पयुजन ही कल्पयुजन है। दरअसल, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा

लगाया। इसी पर भूपेंद्र चौधरी ने तिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "कांग्रेस के लोग भ्रम में हैं। इस पार्टी में कल्पयुजन ही कल्पयुजन है। ये

उन्होंने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, "योगी जी संत आदमी हैं। उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है। वह संवैधानिक पद पर हैं। वह 'सबका साथ और सबका विकास' के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। उनकी हमेशा से ही कोशिश रही है कि समाज में सर्वांगीण विकास हो। समाज के अंतिम पक्ति पर बैठे लोगों तक विकास पहुंच सके।

हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त है।" उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी के सदस्यता अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। पहले

भारत जोड़ो यात्रा राजनीतिक कम और सामाजिक ज्यादा - दिग्विजय

नई दिल्ली, एजेसी। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोमवार को चुनावी राज्य हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा के संदर्भ बोले। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी राज्य हरियाणा में सोमवार से अपनी यात्रा शुरू की है। उनकी यात्रा हरियाणा के उन स्थानों से होकर गुजर रही है, जिसको भाजपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा? इस सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने बताया कि यात्राओं का अपना अलग-अलग महत्व होता है। धार्मिक यात्राएं अलग होती हैं, सोमन वांग चुक जी जो

यात्रा कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। वहीं राजनीतिक यात्रा अलग होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जो उन्होंने कन्या कुमारी से कश्मीर तक की थी, वो राजनीतिक कम और सामाजिक ज्यादा थी। देश में जो नफरत का भाव था, उसको प्रेम और सद्भाव में बदलने के लिए राहुल गांधी ने ये यात्रा की थी। वहीं, जहां तक चुनाव की बात है, तो इसमें हर कोई अपनी यात्रा और जनसभाओं को करता है, वो अलग है। बता दें कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार से चुनावी राज्य हरियाणा में चुनावी यात्रा की शुरुआत की। पार्टी ने इस यात्रा का नाम शहरियाणा विजय

संकल्प यात्रा रखी है। राहुल गांधी ने हरियाणा में जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर जनसभा की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, हरियाणा में श्रद्ध के दशक का अंत करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ एकजुट, संगठित और समर्पित है। अब प्रदेश में 36 बिरादरियों, सबकी हिस्सेदारी तय करने वाली और न्याय की सरकार बनेगी। 90 विधान सभा सीटों वाले हरियाणा में पांच अक्टूबर को मतदान होना है।

संविधान खत्म करना चाहती है भाजपा - राहुल गांधी

हरियाणा, एजेसी। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि हर कोई जानता है कि यहां ड्रप्स का मुद्दा है। मैं मोदी जी से पूछता हूं कि जब अडानी के मुद्रा पोर्ट पर हजारों किलो ड्रप्स पकड़ी गईं, तो आपने क्या कार्रवाई की? उन्होंने दावा किया कि जब हम सत्ता में आएंगे, तो 1200 रुपये में बिकने वाला (एलपीजी) गैस सिलेंडर अब 500 रुपये प्रति सिलेंडर पर उपलब्ध होगा। हम हरियाणा के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी देंगे। राहुल ने कहा कि हरियाणा के लोग सेना में जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना लाकर इस रास्ते को भी बंद कर दिया है। अग्निवीर योजना हिंदुस्तान के जवानों से पेंशन, कैंटीन और शहीद का दर्जा

चोरी करने का तरीका है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, गरीबों को जो भी मिला है, वो सभी संविधान की देन है। लेकिन भाजपा

वंचितों को जगह नहीं देते- वो संविधान पर आक्रमण करते हैं। जब नरेंद्र मोदी, अडानी-अंबानी की मदद करते हैं और हिंदुस्तान में रोजगार का

रक्षा करते हैं। उन्होंने दावा किया कि आज के हिंदुस्तान में कुछ चुनिंदा अरबपतियों के पास सारा पैसा जा रहा है। वहीं पेट्रोल-डीजल, प्याज जैसी चीजों के दाम बढ़ाकर आपकी जेब से लगातार पैसा निकाला जा रहा है। किसी एक सामान के लिए जितनी जीएसटी अडानी-अंबानी देते हैं, उतनी ही जीएसटी देश का सबसे गरीब किसान भी देता है। इसलिए मैंने मन बना लिया है- जितना पैसा नरेंद्र मोदी अडानी-अंबानी को देंगे, उतना ही पैसा हम देश के किसानों, गरीबों और महिलाओं को देंगे। संविधान में लिखा है- हिंदुस्तान के सभी नागरिक एक समान हैं। लेकिन... जब नरेंद्र मोदी अरबपतियों का लाखों- करोड़ का कर्ज माफ करते हैं और गरीब, महिला, किसान का कर्ज माफ नहीं करते, तो वो संविधान पर हमला है।



हमेशा संविधान पर आक्रमण करती रहती है। उन्होंने कहा कि जब आरएसएस के लोग देश के संस्थानों में अपने लोगों को भरते हैं और गरीबों

सिस्टम खत्म करते हैं- वो संविधान पर आक्रमण करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा संविधान को खत्म करती है, हम संविधान की

संपादकीय

भ्रष्टाचारियों का कवच

वादे हैं वादों क्या, भ्रष्टाचार को लेकर कुछ ऐसी ही हालत भारत की है। भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक दल बड़े-बड़े दावे करते हैं। भाजपा गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया था। इसी तरह विपक्षी दलों ने भी केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को निशाने पर रखा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के भ्रष्टाचार पर एक—दूसरे पर जबरदस्त प्रहार के बावजूद यह मुद्दा सुरसा के मुंह की तरह लगातार फ़ैलता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार की इस गंगोत्री से कोई अछूता नहीं है। भ्रष्टाचार का जड़ से ख़त्म करना तो दूर बल्कि सत्तांत्र भ्रष्टाचारियों की ढाल बन कर खड़ा है। इसमें कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं हैं। देश को खोखला करने वाले इस धीमे जहर को संरक्षण देने में केंद्र और राज्यों की सरकारों पीछे नहीं हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने 212 मामलों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए 543 अफसरों व कार्मिकों पर अभियोजन स्वीकृति लंबित है। सीबीआई के कामकाज पर निगरानी रखने वाले केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की सरकारों में अभियोजन स्वीकृति के 41 मामले शामिल हैं जिनमें 149 अधिकारी भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ की गईं। इसके बाद दिल्ली के स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ शिकायतें मिलीं। रिपोर्ट के अनुसार, 202३ में सभी श्रेणी के अधिकारियोंकर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कुल 74,203 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 66,373 का निपटारा कर दिया गया और 7,830 शिकायतें लंबित हैं। सीवीसी की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों में अभियोजन स्वीकृति के सबसे ज्यादा 75 मामले लंबित हैं जिनमें 197 भ्रष्ट अफसर—कार्मिक फंसे हैं। इनमें वित्तीय सेवा विभाग के 53 मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति लंबित है। वित्त मंत्रालय के बाद रक्षा, रेल, शिक्षा तथा कार्मिक मंत्रालयों में लंबित मामलों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। राज्य सरकारोंकेंद्रशासित प्रदेशों में 249 अधिकारियों में सैकड़ों अफसरों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। राज्योंकेंद्रशासित राज्यों में कुल 41 भ्रष्टाचार के मामलों 149 अधिकारी आरोपित हैं। इनमें महाराष्ट्र में 3 मामलों में 41 अधिकारी, उत्तर प्रदेश में 10 मामलों में 31, प. बंगाल में 4 मामलों 25, केंद्रशासित जम्मू—कश्मीर में 4 में 19, पंजाब में 4 में 6, मध्यप्रदेश में 1 भ्रष्टाचार के प्रकरण में एक अिाकारी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक नियमों के अनुसार सीबीआइ से प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अधिकतम तीन माह में अभियोजन स्वीकृति देने का प्रयास किया जाना चाहिए लेकिन लंबित मामलों में 249 अधिकारियों के खिलाफ 81 मामले तीन माह की अवधि से अधिक पुराने हैं। सीवीसी की रिपोर्ट में उन मामलो का भी जिक्र किया है जिनमें जांच में दोषी पाए गए अफसरों के खिलाफ आयोग की सिफारिशों को भी दरकिनार कर दिया गया। इनमें विभिन्न मंत्रालयों और केंद्र सरकार के अधीन संस्थाएं (पीएसयू—बैंक आदि) शामिल हैं। सीवीसी केंद्रीय मंत्रालयों और पीएसयू—बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के जरिये भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर नजर रखता है। सीवीसी ने कहा है कि कुछ संगठन आयोग की सलाह पर अमल करने और आरोपी अधिकारी को चार्जशीट जारी करने में देरी करते हैं। इससे कई मामलों में दोषी अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाता है और समय सीमा चूकने के कारण कोई भ्रष्ट अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। गौरतलब है कि सरकारी विभागों में विषयबत की तरह बढ़ते भ्रष्टाचार पर भारत विश्व में कलकित हो रहा है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 202३ के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर रहा। जबकि वर्ष 2022 में भारत की रैंक 85 वीं थी। अर्थात भारत में भ्रष्टाचार की रफतार थमी नहीं है। इसमें तेजी आई है। इस सूचकांक में भारत आठ पायदान आगे बढ़ गया। वर्ष २०२३ की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में पाकिस्तान (133) और श्रीलंका (115) अपने अपने कर्ज के बोझ तले दबे हैं और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि दोनों देशों में मजबूत न्यायिक निगरानी है, जो सरकार को नियंत्रण में रखने में मदद कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन (76) ने पिछले दशक में भ्रष्टाचार के लिए 37 लाख से अधिक का सार्वजनिक अधिकारियों को दंडित करके अपनी आक्रामक भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई से सुर्खियां बटोरीं। भ्रष्टाचार से देश एक भी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अछूता नहीं है। केंद्र हो या राज्यों में चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकारें हों, किन्तु एक भी सत्तारूढ़ दल यह दावा नहीं कर सकता की कोई भी एक विभाग पूर्णतः भ्रष्टाचार से मुक्त हो सका है। देश की तरक्की में बाधक बना यह मुद्दा सिर्फ शोर—शराबे तक ज्यादा सीमित है। जमीनी स्तर पर कोई भी राजनीतिक दल इसके जड़ सहित ख़त्मे की दिशा को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के मामलों सिर्फ नौकरशाह ही शामिल हैं। राजनेता भी इसमें पीछे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों के गठजोड़ के कारण ही भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है।

उत्तराखंड ने भू-कानून की आशा फिर जगा दी

जयसिंह अब तक भू-कानून की मांग को लेकर मौन धारण करने वाले उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले बजट सत्र में राज्य के लिए एक सशक्त भू-कानून लाने की घोषणा कर ही दी। हिमालयी राज्यों में उत्तराखण्ड अकेला राज्य है जहां कठोर कानून के अभाव में जमीनों की खरीद फरोख्त सबसे आसान है। उत्तराखण्ड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर गैर कृषकों द्वारा कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक के लिए कानून अवश्य बना था लेकिन ऐसा कानून बनाने वाली राज्य की पहली निर्वाचित तिवारी सरकार ने ही उस कानून में धारा दो जोड़कर पहला छेद कर डाला था। सन् 2017 के बाद तो भूखोरों और भूमि व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए उस कानून में बार-बार संशोधन की कानून का केवल कंकाल ही बाकी छोड़ा गया था।

भू-कानून का 2017 के बाद बना

नया भूमि प्रबंधन कानून बनाने के लिए गठित पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता वाली समिति अपनी रिपोर्ट 5 सितम्बर 2022 को सौंप चुकी थी लेकिन उस रिपोर्ट को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया था। इसलिए आम े कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक के लिए कानून अवश्य बना था लेकिन ऐसा कानून बनाने वाली राज्य की पहली निर्वाचित तिवारी सरकार ने ही उस कानून में धारा दो जोड़कर पहला छेद कर डाला था। सन् 2017 के बाद तो भूखोरों और भूमि व्यापारियों को लाभ पहुंचाने

आदित्य पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के अपने फंसले पर आगे बढ़ने और संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान में संशोिान के लिए तीन विधेयक पेश करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अब, सवाल यह उठता है कि क्या वह इन संशोधनों को लोकसभा में पारित करवा पाएगी, जहां उसके पास दो—तिहाई बहुमत नहीं है। क्या विपक्ष इस विधेयक को आसानी से पारित होने देगा? कांग्रेस और इंडी ब्लॉक इसके सख्त खिलाफ हैं और कार्यवाही को रोक सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके पास भी कानूनी दिग्गज हैं जो ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के खिलाफ मजबूत तर्क दे सकते हैं। लेकिन फिर एनडीए को लगता है कि तीनों विधेयकों को 50 प्रतिशत राज्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। केवल स्थानीय निकायों को संरक्षित करने से संबंधित विधेयक को कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों के समर्थन

शहरों की ओर आने को मजबूर हैं जंगली जानवर

विनोद प्रसिद्ध शिकारी एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट का नाम आपने सुना होगा, जिनके नाम पर उत्तराखंड में नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट शिकारी थे और वो इसलिए प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने 33 नरभक्षी बाघ और तेंदुओं को मारकर उत्तराखंड (तब यूनाइटेड प्रोविंस) के लोगों को आदमखोर जानवरों से निजात दिलाई थी। इन दिनों भी देश के अलग-अलग राइजों में कई जानवर आदमखोर हो गए हैं। राजस्थान का उदयपुर हो या उत्तर प्रदेश का बहराइच और लखीमुपर खीरी, इंसान बाघ, तेंदुओं और भेड़ियों से भयभीत हैं। आखिर को क्या कारण है, जो वन्यजीव इंसानी खून के प्यासे हो गए हैं और मानव

का शिकार करने निकल पड़े हैं?

शहरों की ओर क्यों रुख कर रहे हैं जानवर? उदयपुर में इन दिनों तेंदुए ने आतंक मचाया हुआ है। वो अब तक सात लोगों की जान ले चुका है। वन्य विभाग इस आदमखोर तेंदुए को पकड़ने में नाकाम रहा है, क्योंकि अब तक उसने जो तेंदुए पकड़े गए हैं, वो संभवतः आदमखोर नहीं थे, क्योंकि उनके पकड़े जाने के बाद भी इंसानों का मरना जारी है। उदयपुर जैसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के बहराइच की भी है, जहां आदमखोर बन चुके भेड़िए आए दिन शिकार कर रहे हैं। उन्होंने कई बच्चों को अपना निशाना बनाया है। दर्जनों लोग उनके हमले में घायल हो चुके

केंद्र की ‘धरोहर अपनाओ’ योजना

संजय नया भारत सत्तारूढ़ शासन की निगरानी में शैक्षणिक संशोधनवाद का गवाह रहा है, जिसके कारण पाठ्यपुस्तकों में देश के इतिहास को नष्ट किया गया है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की विरासत के अभिन्न अंग कुछ विशिष्ट वास्तुशिल्प चमत्कारों को एक अन्य प्रकार के संशोधनवाद द्वारा कमजोर किया जा रहा है, जो इन स्मारकों के भौतिक और पर्यावरणस्वयं, संदर्भ संबंधी चरित्रों में परेशान करने वाले परिवर्तनों को पेश करने की धमकी देता है। इस प्रकार, हुमायूँ के मकबरे के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर एक बहिष्ण में भोजनालय – एक यूनेस्को विश्व े रोहर स्थल – इसके पश्चिमी प्रवेश द्वार पर एक कैफे, इमारत से सटे लिएट, एक ध्वनि और प्रकाश शो और साथ ही इसके बगीचों में निजी भोजन – जाहिर तौर पर डालमिया भारत के विजन डॉक्यूमेंट की योजनाओं में शामिल हैं, एक कॉर्पोरेट इकाई, जिसने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की विरासत को अपनाने

की योजना के तहत 16वीं सदी की इमारत को अपनाया है। अगर ऐसा होता है, तो नुकसान केवल हुमायूँ के मकबरे तक ही सीमित नहीं होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ अपने समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में, डालमिया भारत को पुराना किला, सफदरजंग का मकबरा और महरोली पुरातत्व पार्क जैसे अन्य स्थलों का काम सौंपा गया है। देश के 66 स्मारकों को कवर करने वाले 19 समझौता ज्ञापनों में से, जिन पर एएसआई ने कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ हस्ताक्षर किए हैं, केवल डालमिया भारत को, बेजह, इन के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर एक बहिष्ण में व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति दी गई है।

संरक्षणवादी और इतिहासकार इस लिएट, एक ध्वनि और प्रकाश शो और साथ ही इसके बगीचों में निजी भोजन – जाहिर तौर पर डालमिया भारत के विजन डॉक्यूमेंट की योजनाओं में शामिल हैं, एक कॉर्पोरेट इकाई, जिसने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की विरासत को अपनाने

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

विचार

संसद के शीतकालीन सत्र को गर्म करने के लिए एक चुनावी मुद्दा

की आवश्यकता होगी। इसलिए, उसे लगता है कि उसे ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ योजना को लागू करने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ना



चाहिए। सत्तारूढ़ एनडीए नेतृत्व को लगता है कि वे संविधान संशोधान विधेयक को आसानी से पारित करवा सकते हैं जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एह साथ कराने से संबंधित है। उच्चाधिकार प्राप्त

समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाली सरकार का मानना छ्दे कि उसे ‘नियत तिथि’ से संबंधित उप—खंड (1) जोड़कर अनुच्छेद



82ए में संशोधन करना चाहिए। वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति से संबंधित अनुच्छेद 82ए में उप—खंड (2) भी शामिल करना चाहेगी। केंद्र को अनुच्छेद 83(2) में संशोधन

है। वन विभाग ने कई भेड़िए पकड़े हैं, लेकिन आतंक रूकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के लखीमुपर खीरी में एक बाघ का आतंक लगातार बढ़ रहा है। जंगली जानवरों के आदमखोर बनने के पीछे कई वजह हैं। मुख्य रूप से जंगलों का सिकुड़ना और शिकार की उपलब्धता कम होना एक मुख्य कारण है।

जंगलों के आसपास या जंगलों के भीतर तक इंसान ने अपनी बस्तियां बसा रखी हैं। इंसान की गतिविधियां जंगल में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जब जंगली जानवर को वनक्षेत्र में पर्याप्त शिकार नहीं मिलता है तो वो इंसानी बस्तियों की ओर रुख करता है और इंसान को अपना शिकार बना लेता है। कुछ वृद्ध जानवर भी

करना होगा और लोकसभा की अवधि 1 और विघटन से संबंधित नए उप—खंड (3) और (4) शामिल करने होंगे। उसे विधानसभाओं को भंग



करने और ‘एक साथ चुनाव’ शब्द जोड़ने के लिए अनुच्छेद 327 में भी संशोधन करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विधेयक को कम से कम 50 प्रतिशत लोगों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन, एनडीए सरकार को राज्य मामलों से संबंधित दूसरे संविधान संशोधन विधेयक को लेकर समस्या होगी क्योंकि इसे कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित करना होगा। चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन करना होगा, खासकर स्थानीय निकायों के लिए। यहां, संख्या के खेल के अलावा एक समस्या यह भी है कि चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग अलग—अलग निकाय हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की है, लेकिन जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, पंचायतों और विधान परिषदों की बात आती है, तो चुनाव आयोग ही जिम्मेदार होता है। उच्चस्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि एक समान मतदाता सूची होनी चाहिए। विचार अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग

होगी। विकास की अंधाधुंध दौड़ में इंसान जंगलों को लगभग काट चुका है। आखिर जानवर जाएं तो जाएं कहाँ? कभी भारत में जंगल ही जंगल थे, लेकिन आज देश में जानवरों के लिए चंद नेशनल पार्क बनाकर छोड़ दिए गए हैं, लेकिन इंसान या तो उसे पकड़कर पिंजरों में डाल देता है या उसे मार डालता है। आदमखोर जानवरों को मारने के लिए कानून भी है, जिसके तहत किसी जानवर को आदमखोर घोषित किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के सेक्शन 11 के अनुसार ऐसा जानवर जो इंसानों के जीवन के लिए खतरा हो गया है, उसे आदमखोर बताकर मारा जा सकता है। देश की आबादी लगातार

बढ़ रही है। विकास की अंधाधुंध दौड़ में इंसान जंगलों को लगभग काट चुका है। आखिर जानवर जाएं तो जाएं कहाँ? कभी भारत में जंगल ही जंगल थे, लेकिन आज देश में जानवरों के लिए चंद नेशनल पार्क बनाकर छोड़ दिए गए हैं, लेकिन इंसान या तो उसे पकड़कर पिंजरों में डाल देता है या उसे मार डालता है। आदमखोर जानवरों को मारने के लिए कानून भी है, जिसके तहत किसी जानवर को आदमखोर घोषित किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के सेक्शन 11 के अनुसार ऐसा जानवर जो इंसानों के जीवन के लिए खतरा हो गया है, उसे आदमखोर बताकर मारा जा सकता है। देश की आबादी लगातार

बढ़ रही है। विकास की अंधाधुंध दौड़ में इंसान जंगलों को लगभग काट चुका है। आखिर जानवर जाएं तो जाएं कहाँ? कभी भारत में जंगल ही जंगल थे, लेकिन आज देश में जानवरों के लिए चंद नेशनल पार्क बनाकर छोड़ दिए गए हैं, लेकिन इंसान या तो उसे पकड़कर पिंजरों में डाल देता है या उसे मार डालता है। आदमखोर जानवरों को मारने के लिए कानून भी है, जिसके तहत किसी जानवर को आदमखोर घोषित किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के सेक्शन 11 के अनुसार ऐसा जानवर जो इंसानों के जीवन के लिए खतरा हो गया है, उसे आदमखोर बताकर मारा जा सकता है। देश की आबादी लगातार

और राज्य चुनाव आयोगों के बीच काफी समन्वय की आवश्यकता होती है। यह किस हद तक संभव है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। राज्यों से संबंधित मुद्दों पर दो विचार हैंरूक दो चरणों में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ आयोजित किया जाए। कुछ लोगों का मानना छ्दे कि इन मुद्दों के लिए एक साधारण विधेयक पेश किया जा सकता है और इसके लिए राज्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। लेकिन यह राजनीतिक और कानूनी विवाद में पड़ सकता है। इस पर बहुत कानूनी मंथन करना होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर सकता है। उच्चस्तरीय समिति ने पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने और दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर पंचायतों और नगर निकायों जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का सुझाव दिया है। यह मुद्दा निश्चित रूप से संसद के शीतकालीन सत्र में गरमाहट पैदा करेगा।

जानवरों को भी पृथ्वी पर रहने का उतना ही अधिकार है, जितना इंसानों को है। यदि जानवर नहीं रहेंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। पहले ही बड़ी संख्या में वन्यजीव विलुप्त हो चुके हैं और कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। सरकारों को केवल कानून बनाकर अपने काम की इतिश्री नहीं करनी चाहिए। कानूनों की सख्ती से पालना और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।

ईमानदारी से जानवरों को उनका इलाका सौंपने की जरूरत है। यदि ऐसा न हुआ और विकास की अंधी दौड़ चलती रही तो वन्यजीवों का आदमखोर बनना जारी रहेगा। इंसान और जानवरों की लड़ाई यूं ही चलती रहेगी।

150 साल पुरानी ट्राम सेवा बंद

अजय

ट्राम, जो कलकत्ता की प्रतीकात्मकता का पर्याय बन गया है, अपने अस्तित्व के 151वें वर्ष में पूरी तरह से बंद होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि शहर की सबसे पुरानी स्ट्रीटकार सेवा, जो उपेक्षा और आधुनिक, तेज परिवहन साधनों के लोकप्रिय होने के कारण धीरे-धीरे खत्म हो रही है, अब एक ही मार्ग पर चलेगी – 2015 में 25 मार्गों से कम – जो एक सुशोभित विरासत पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करेगा। यह राज्य सरकार के पहले के रूख के बिल्कूल विपरीत है जिसमें उसने पिछले साल कलकत्ता उच्च न्यायालय को एक हलफनामे में ट्राम को पुनर्जीवित करने का इरादा जताया था। सरकार का नवीनतम निर्णय परिचालन संबंधी मुद्दों, बढ़ते आर्थिक घाटे, बड़े के पुराने बुनियादी ढांचे, सिकुड़ते सड़क स्थान और कारों की बढ़ती संख्या जैसे विचारों पर आधारित प्रतीत होता है। इसके अलावा, शहर के मुखियाओं ने तर्क दिया है कि ट्राम यातायात जाम का कारण बनते हैं, खासकर शहर के उत्तरी हिस्सों में जहां सड़कें संकरी हैं, जबकि ऐसा कोई विश्वसनीय अध्ययन नहीं है जो यह दिखाए कि ट्राम यातायात जाम का कारण बनते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि पुलिस ट्राम चलाने के प्रति उदासीन है। इस मामले पर कई यात्रिकाओं पर सुनवाई कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के फ़ैसले का ट्राम के भविष्य पर गहरा असर पड़ेगा। कलकत्ता की ट्राम कारों के प्रति संस्थागत और सामूहिक मोहभंग अजीब है। कलकत्ता, जैसा कि अक्सर होता है, धारा के विपरीत तैरता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि दुनिया भर में ट्राम को सार्वजनिक परिवहन के स्वच्छ, किफायती साधन के रूप में फिर से तैयार किया जा रहा है और फिर से शुरू किया जा रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्राम सेवाएं अब लगभग 400 देशों में फिर से उभर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए उन पर निर्भर हैं। चीन में ट्रैकलेस ट्राम की लोकप्रियता बढ़ी है, जहाँ बहुत अधिक आबादी है। 21वीं सदी में वाहनों के प्रदूषण को दूर करने में आधुनिक ट्राम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अधिकारियों की ओर से ट्राम को अवशेष या, सबसे अच्छे रूप में, सौम्य विरासत के रूप में पेश करना अनुचित है। भारत के महानगरों में कलकत्ता में वाहनों का घनत्व सबसे अधिक है। निजी वाहनों की संख्या में भी तेज वृद्धि देखी गई हैरू 2011 और 2022 के बीच पंजीकृत कारों की संख्या 21 लाख से बढ़कर 51 लाख हो गई है। ट्राम न केवल परिवहन में भीड़भाड़ कम करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल और किफायती परिवहन साधन भी हैं। इनका न्यूनतम परिचालन व्यय और लंबी सेवा अवधि अन्य प्रोत्साहन हैं। ट्राम को बंद करने के बजाय उनका आधुनिकीकरण ही आगे का रास्ता होना चाहिए।

कृषिभूमि

औद्योगीकरण के नाम पर कानून में ढील दिए जाने से सन् 2018 से लेकर अब तक उत्तराखण्ड की प्राइम लैंड लगभग बिक चुकी है। जमीनों की बेतहाशा खरीद फरोख्त नगरीय क्षेत्रों और उनके आसपास ही हुई है, इसलिए भूमि कानून में धारा —2 रखी गई थी। उस धारा के अनुसार कृषि भूमि की खरीद पर अंकुश वाला प्रावधान नगर निकाय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। जबकि पहले अध्यादेश वर्ष 2003 संख्या 6 में समस्त उत्तरांचल पर यह बंदिश लागू करने का प्रधान रखा गया था। इस धारा का लाभ भी सौदागरों को पहुंचाने के लिए सन् 2017 में ही प्रदेश के 1३ में से 12 जिलों के ३85 गावों को 45 नगर निकायों में शामिल कर 50,104

कृषिभूमि

कृषिभूमि

हेक्टअर जमीन को खरीद फरोख्त की बंदिशों से मुक्त कर दिया गया था। राज्य सरकार के इस निर्णय से अकेले गढ़वाल मण्डल में देहरादून जिले में सर्वाधिक 85 ग्रामों के 20221.294 हेक्टयर ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम के अतिरिक्त हरबर्तपुर, विकास नगर, ऋषिकेश, धारा—2 रखी गई थी। उस धारा के अनुसार कृषि भूमि की खरीद पर अंकुश वाला प्रावधान नगर निकाय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। जबकि पहले अध्यादेश वर्ष 2003 संख्या 6 में समस्त उत्तरांचल पर यह बंदिश लागू करने का प्रधान

रखा गया था। इस धारा का लाभ भी सौदागरों को पहुंचाने के लिए सन् 2017 में ही प्रदेश के 1३ में से 12 जिलों के ३85 गावों को 45 नगर निकायों में शामिल कर 50,104

उत्तराखण्ड अकेला हिमालयी राज्य है जहां जमीनों की बिकवाली और दलाली का धन्धा सर्वाधिक फलफूल रहा है। उत्तराखण्ड की व्यावसायिक और आवासीय महत्व की सभी जमीनें भूखोरों के चंगुल

में चली गई हैं और सर्वाधिक आमदनी वाला प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय उत्तराखण्ड में दिन दुगुनी और रात चौगुनी रफतार से फलफूल रहा है। यहां तक कि बड़ी संख्या में राजनीतिक लोग भी इस धन्धे में प्रत्यक्ष और पर्यक्ष रूप से शामिल हैं। फिर भी अगर सरकार सचमुच एक सशक्त भूमि कानून बना रही है तो उसे सरकार का रस से आया हुआ दुरुस्त फ़ैसला माना जा सकता है, बशर्ते सरकार जनभावनाओं के अनुकूल और व्यवहारिक कानून बना दे। अगर सरकार उत्तराखण्ड में उपान्तरित और अनुकूलित जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम—1950 में 2017 के बाद के सभी संशोधन समाप्त कर देती है तो भी पूरा मकसद हल नहीं होता।

संस्कार भारती की तृतीय मासिक योजना बैठक संपन्न



ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। संस्कार भारती जौनपुर की तृतीय मासिक योजना बैठक दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को संस्था के आय व्यय निरीक्षक श्री राजेश किशोर जी एवं साहित्य विधा प्रमुख श्री आलोक रंजन सिन्हा जी के संयुक्त संयोजन में उनके आवास पर संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ संस्था के ध्येय गीत से हुआ।बैठक में विगत माह में संस्था द्वारा कराए गए कार्यक्रमों की समीक्षा हुई तथा आगामी होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में संस्थाध्यक्ष डॉ ज्योति सिन्हा जी को जीवन स्मृति सभा जौनपुर द्वारा संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश में माननीय सदस्य मनोनीत होने पर अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से संस्था के संरक्षक श्री रविन्द्र जी ,प्रांतीय महामंत्री श्री सुजीत जी , उपाध्यक्ष विष्णु जी, ऋषि जी ,सहकोषाध्यक्ष मनीष जी ,संजय जी ,आशीष श्रीवास्तव , मयंक नारायण , आशीष साहू , अजय गुप्ता , गौरव श्रीवास्तव, दिलीप सिंह ,प्रदीप सिंह, शशाक सिंह राजू, अवधेश

यादव, सुप्रतीक गुप्ता, बालकृष्ण साहू, अवधेश श्रीवास्तव, रविकांत जायसवाल, आशीष जायसवाल , जय सिंह, अतुल सिंह , गणतंत्र श्रीवास्तव, मनोज गुप्ता व श्रीमती साक्षी श्रीवास्तव आदि सदस्य उपस्थित रहे।बैठक का संचालन एवं आभार जिला महामंत्री अमित गुप्ता ध्ंशुण ने किया। बैठक का समापन कल्याण मंत्र से हुआ।

दुष्कर्म के बाद प्रदर्शन के दौरान हुई मार पीट पर छात्रों को किया गया सरपेंड

वाराणसी, संवाददाता। आईआईटी बीएचयू में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का विरोध और पीड़िता के लिए न्याय मांगने वाले छात्र-छात्राओं को बीएचयू प्रशासन द्वारा निलंबित कर दिया गया गया है। प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई छात्रों के खिलाफ की गई है, जो मौजूदा सरकार की नीतियों से असहमति रखते हैं। कैंपस में हमेशा समाज या अन्य जरूरी सवालों पर मुखर रहे हैं।

लाइब्रेरी की सुविधा भी छिनी विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को 15–30 दिनों के लिए ही

आईजीआरएस निस्तारण में लापरवाही बरतना औराई कोतवाली के उप निरीक्षक को भारी पड़ा

भदोही, संवाददाता। भदोही के ज्ञानपुर में आईजीआरएस पोर्टल पर मामलों के निस्तारण को लेकर लापरवाही करना औराई कोतवाली के उप निरीक्षक को भारी पड़ गया। जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने निलंबन का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार आईजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद फर्जी रिपोर्ट लगाई गई जिसके बाद शिकायत हुई और जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई सामने आई। ज्ञानपुर में शासन की प्राथमिकताओं में शामिल आईजीआरएस निस्तारण में लापरवाही बरतना औराई कोतवाली के उप निरीक्षक को

निलंबित किया है। इस दौरान इन छात्रों को हॉस्टल, लाइब्रेरी और एचआरए की सुविधा से भी बेदखल कर दिया गया है। इसके अलावा इस समय में प्रदर्शनकारी छात्रों की काउंसलिंग करने और उनसे कम्प्युनिटी सर्विस कराने का आदेश दिया गया है।

ये था मामला पिछले साल 1 नवंबर की रात आइआइटी बीएचयू कैंपस में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। सिंह द्वार पर इस मामले का विरोध करने वाले दो संगठनों एबीवीपी और भगत सिंह छात्र मोर्चा के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इसके बाद कई छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया। अब 11 महीने बाद उनमें से कई छात्रों को बीएचयू ने सरपेंड किया है।

आइजीआरएस निस्तारण में लापरवाही बरतना औराई कोतवाली के उप निरीक्षक को भारी पड़ा

भदोही, संवाददाता। भदोही के ज्ञानपुर में आईजीआरएस पोर्टल पर मामलों के निस्तारण को लेकर लापरवाही करना औराई कोतवाली के उप निरीक्षक को भारी पड़ गया। जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने निलंबन का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार आईजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद फर्जी रिपोर्ट लगाई गई जिसके बाद शिकायत हुई और जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई सामने आई। ज्ञानपुर में शासन की प्राथमिकताओं में शामिल आईजीआरएस निस्तारण में लापरवाही बरतना औराई कोतवाली के उप निरीक्षक को

भारी पड़ गया। फर्जी रिपोर्ट लगाने पर उप निरीक्षक शमशाद खां को पुलिस अधीक्षक डॉ. मीनाक्षी कात्यायन ने मंगलवार को निलंबित कर दिया। उन्हां ने अन्य जांचकर्ताओं को सख्त हिदायत दिया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाए अन्धथा कठोर कार्रवाई तय होगी। औराई कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने एक आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। जिसकी जांच उप निरीक्षक शमशाद खां को दी गई। उप निरीक्षक की ओर से आईजीआरएस प्रार्थना पत्र की जांच के दौरान बिना आवेदिका के

गोरखपुर, संवाददाता। प्रदेश सरकार के प्रयासों के साथ-साथ सामुदायिक सहभागिता से इंसेफेलाइटिस नियंत्रित हुआ है। अब अन्य संचारी रोगों पर भी नियंत्रण पाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने में जनजागरूकता और साफ सफाई का विशेष महत्व है। प्रदेश सरकार के इस संदेश के साथ सोमवार को विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ एनेक्सी भवन से पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, चित्तूपार विधायक राजेश त्रिपाठी, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह और सांसद प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह ने किया। इस अभियान में 11 अक्तूबर से घर-घर दस्तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम बुखार, टीबी,

मिशन शक्ति फेज-5 का शुभारम्भ हुआ



ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा-निर्देशानुसार मिशन शक्ति फेज-5 का शुभारम्भ जनपद जौनपुर में किया गया। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जू-जून्सू खेल में देश की तरफ से विश्व चौम्भियनशिप जो ग्रीस में 22–28 अक्टूबर, 2024 तक आयोजित हो रहा है। जनपद

जौनपुर की सुश्री नम्रता यादव पुत्री स्व० अमरनाथ यादव ग्राम तियरा, पी० बदलापुर, जौनपुर खेल मे उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि हेतु जनपद जौनपुर में बालिकाओं को खेल में प्रेरणा देने के लिए 51000 रू० की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी साथ ही उ०प्र० खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति जौनपुर द्वारा भी 25000 रू० की प्रोत्साहन राशि को बालिका को प्रदान किया गया। जिलाधिकारी डॉ० दिनेश चन्द्र सिंह ने कहा कि उ०प्र०

सरकार खेल प्रोत्साहन पर विशेष रुचि ले रही है। मा० मुख्यमंत्री जी को विजेता खिलाडी को पुस्कार राशि एवं नौकरी प्रदान कर रहे है। इसी के क्रम मे जनपद जौनपुर में बालिका खेल को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन धन राशि प्रदान की गयी है। सुश्री नम्रता का चयन प्रोत्साहन हेतु किये जाने हेतु जनपद के मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम को भी धन्यवाद दिया।

उक्त कार्यक्रम में अपर जिलाधिाकारी (वित्त एवं राजस्व) राम अक्षयबर चौहान, क्षेत्राधिकारी नगर देवेन्द्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय, क्रीडा अधिकारी अतुल सिन्हा, फुटबाल कोच चन्दन सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी चन्दन राय ने प्रतिभाग किया।

इंसेफेलाइटिस की तर्ज पर ही नियंत्रित किए जाएंगे अन्य संचारी रोग – आशुतोष कुमार

फाइलेरिया, कुष्ठ, मधुमेह, कैंसर और हाइपरटेंशन के मरीज दूढ़ेंगी। उद्घाटन समारोह में उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं और सफाईकर्मियों समेत अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को इंसेफेलाइटिस उन्मूलन की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन उपेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर एसीएमओ डॉ एके चौधरी, डॉ वीपी पांडेय, डीटीओ डॉ गणेश यादव, डीआईओ डॉ नंदलाल कुशवाहा, नोडल अधिकारी डॉ राजेश, मंडलीय किटविज्ञानी डॉ वीके श्रीवास्तव, डीएमओ अंगद सिंह, डीएचईआईओ केएन बरनवाल, डीडीएचईआईओ सुनीता पटेल, जेई एईएस कंसल्टंट सिद्धेश्वरी सिंह, डब्ल्यूएचओ,

गण और आदिल फखर के अलावा मलेरिया, फाइलेरिया, टीबी और कुष्ठ विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे।

अब तक एईएस के 44, डेंगू के 63 केस मिले सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दूबे ने बताया कि 14 विभाग मिल कर संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज, नगर निकाय, शिक्षा विभाग, आईसीडीएस, कृषि और चिकित्सा शिक्षा समेत 14 विभाग मिलकर एहत साक्षरता कार्यक्रमों को प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिले में इस वर्ष एक्यूट इंसेफे लाइटिस सिंड्रोम(एईएस) के 44 केस निकले हैं, वहीं जापानीज इंसेफेलाइटिस का कोई मामला नहीं मिला है। अभी तक डेंगू के 63 केस मिले हैं। इस

मतदाता जागरूकता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता विजेता नेहा मौर्य को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित

ब्यूरो प्रमुख विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जौनपुर। सुनियोजित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम (स्वीप) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय आनलाइन स्लोगन प्रतियोगिता की विजेता जमैथा जौनपुर निवासी नेहा मौर्य को जिलाधिकारी डॉ० दिनेश चंद्र सिंह ने प्रशस्ति पत्र, पेन ड्राइव व नगद धनराशि प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित पत्र व पुरस्कार सामग्री को आज विजेता को प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 मे स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमो से प्रचार-प्रसार कराया गया था। इसी क्रम मे विशेषकर युवा मतदाताओं को पंजीकरण हेतु जागरूक किये जाने के दृष्टिगत राज्य स्तरीय आनलाइन पोस्टरस्व्लोगन प्रतियोगिता 1.0 आठ दिसम्बर 2023 से आठ जनवरी 2024 तक थे। प्रतियोगिता की गयी थी, जिसमे 18 से 20 आयु वर्ग के युवा मतदाता तथा सभी दिव्यांग मतदाता भाग ले सकते थे। प्रतियोगिता की थीम-नैतिक मतदान, मतदान क्यों, मतदान प्रतिशत बढ़ाना व केवाईसीध सी-विजिलध्वीएचएक्क्षम ऐप की उपयोगिता थीम थी। पुरस्कार हेतु सिर्फ वही पात्र रहे जिनका नाम पांच जनवरी 2024 को अन्तिम प्रकाशन मतदाता सूची मे दर्ज रहा। आगे जिलाधिकारी ने विजेता दिव्यांग नेहा मौर्या की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि नेहा ने जौनपुर का गौरव बढ़ाया है। इससे युवाओं एवं दिव्यांगों को मतदाता बनने हेतु प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राम अक्षयबर चौहान, उप जिलाधिाकारी ज्ञान प्रकाश, जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर सैय्यद मोहम्मद मुस्तफा, वरिष्ठ सहायक महमूद अली, सीओ सिटी देवेश सिंह, जिला निर्वाचन कार्यालय से रिेशे जायसवाल व अजीत कुमार आदि उपस्थित रहे।

मुठभेड़ के बाद गन्ने के खेत में छिपा शराब तस्कर दबोचा

कुशीनगर, संवाददाता। सोमवार की शाम मुठभेड़ में एक तस्कर के घेर में गोली लग गई। तस्करों की गोली से एक होमगार्ड घायल हो गया और चार शराब तस्कर फरार हो गए। गन्ने के खेत में छिपे घायल तस्कर को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार न कर लिया। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार तस्कर ने अपने साथियों का नाम बताया है, सभी कुशीनगर जिले के रहने वाले हैं। शराब तस्करी के साथ-साथ पशु तस्करी के धंधे में भी आरोपी शामिल हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस टीम ने पडरौना कोतवाली क्षेत्र के खिरकिया में दबिश दी, लेकिन तस्कर हाथ नहीं लगे।

गोपालगंज के कुचायकोट पुलिस को जानकारी मिली कि कुशीनगर जिले के रास्ते बिहार में शराब तस्करों की गाड़ी इंट्री की है। हरकत में आई कुचायकोट की पुलिस सोमवार की देर शाम कोतवाली क्षेत्र के खिरकिया में ले गए, हालत गंभीर बताकर डॉक्टर गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चला। रात होने के चलते तस्कर नहीं पकड़ा जा सका। मंगलवार को सुबह पुलिस ने गन्ने के खेत से सोमवार को सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने तस्कर की पहचान पडरौना घेराबंदी कर एनएच-28 पर वाहन चेंकिंग शुरू कर दिया। लज्जरी वाहन को आता देख पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो चालक ने वाहन की गति तेज कर दी। कुछ दूर आगे पुलिस की दूसरी पुलिस की टीम हाइवे पर वाहन

सांक्षिप्त खबरें

टहलने निकली युवती और छात्रा लापता, केस दर्ज हुआ

गोरखपुर, संवाददाता। एक गांव की एक युवती और छात्रा शनिवार को लापता हो गईं। दोनों के मां की तहरीर पर मंगलवार को कैंपियरगंज थाने में पुलिस छह लोगों पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। दोनों युवतियों की मां ने तहरीर में लिखा है कि शनिवार शाम करीब 6:30 बजे कक्षा आठ में पढ़ने वाली छात्रा 20 वर्षीय युवती के साथ टहलने निकली। आरोप है कि गांव के कुछ मनबढ़ों ने उनका अपहरण कर लिया है। आरोपियों के घर जाने पर वे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है, बहुत जल्द आरोपियों को पकड़कर युवती और छात्रा को दूढ़ निकाला जाएगा।

सभासद की फर्जी आईडी बनाकर भेज रहा आपतिजनक मैसेज- थाने में दी तहरीर

गोरखपुर, संवाददाता। नगर पंचायत वार्ड नंबर चार केशपुर के सभासद की फर्जी आईडी बनाकर एक युवक आपत्तिजनक मैसेज कर रहा है। दूसरी जाति का विरोध करने के साथ गाली गलौज पोस्ट करने पर सभासद परेशान हैं। सभासद ने सोमवार को सहजनवां थाने में तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सभासद लक्ष्मण ने सहजनवां पुलिस को तहरीर देकर बताया कि लुचुई निवासी एक युवक मेरी फर्जी आईडी बनाकर उसमें मेरी फोटो लगाई है। उस आईडी से सोशल मीडिया व फेसबुक पर असामाजिक मैसेज, दूसरी जाति का विरोध व गाली-गलौज लिखकर भेज रहा है। मैसेज पाकर लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मुझे समाज में बदनाम किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम ऑफिस में सीबीआई का छापा

वाराणसी, संवाददाता। पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय लहरतारा में लखनऊ सीबीआई की टीम ने छापा मारा। मंगलवार की दोपहर धमकी सीबीआई की टीम ने कार्यालय में तैनात सीनियर डीईएन टू सत्यम सिंह को दो लाख 20 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। अधिकारी के घर से कैश, आभूषण और लग्जरी आइटम सीबीआई की जांच में मिले हैं। रेलवे ट्रेक परियोजना के बिल भुगतान में हीलाहवाली और कमीशनबाजी का मामला बताया जा रहा है। ट्रेक के कार्य में बिल पास करने के एवज में लंबे समय से कमीशन की मांग का आरोप है। फिलहाल सीबीआई ने अधिकारी के लैपटॉप, रजिस्टर और मोबाइल को कब्जे में लिया है। कई फाइलों और रिकॉर्ड को खंगाले गए हैं। सीबीआई की धमक की सूचना से पिछले डेढ़ वर्ष से अधिक समय से मंडल में तैनात इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी के करीबियों ने अपने-अपने मोबाइल रिचर्ज कर लिए। डीआरएम बिल्डिंग में छापा से कई ठेकेदार और अधिकारी दोपहर बाद ही खिंसक लिए। मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं।

सोशल मीडिया की अभद्र टिप्पणियों पर लगेगा लगाम

वाराणसी, संवाददाता। आईआईटी बीएचयू में सोशल मीडिया प्लेटफार्म की अभद्र टिप्पणी पर लगाम लगाने के लिए एआई सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इससे भारत की अलग अलग भाषाओं में होने वाली साइबर बुलिंग पर लगाम लगाई जा सकेगी। ये तकनीक डिजिटल और सोशल मीडिया पर अपमानजनक शब्दों को ट्रैस करेगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों ने देवनागरी-रोमन मिश्रित टेक्स्ट का विश्लेषण किया। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. रविंद्रनाथ चौधरी सी. ने बताया कि भारत, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डिजिटल आबादी का घर है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस पर देश की जनता काफी सक्रिय रहती है। लेकिन इसके साथ ही ये यूजर्स के साइबर बुलिंग (अभद्र सामग्री) भी करते हैं। बताया कि यहां के यूजर्स सेंट्रियल अक्सर बहुभाषीय होती है, जो हिंदी और अंग्रेजी जैसे भाषाओं के मिश्रण का उपयोग करती है। केवल एक भाषा में ही अभद्र सामग्री की पहचान करना दिक्कत की बात है और जब यह मिश्रित-भाषा की होती है, तो यह और भी जटिल हो जाती है।

बीएचयू अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट

वाराणसी, संवाददाता। एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत ने बीएचयू ओपीडी में छह वर्ष पूर्व हार्निया का इलाज कराने गए तत्कालीन छात्र आकाश मिश्र पर हमला करने के मामले में आरोपी डॉ. उदय कांत सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने इसके पहले 23 जुलाई 2024 को आरोपी डॉक्टर की तरफ से आरोप से डिस्चार्ज किए जाने के आवेदन को खारिज करते हुए सोमवार को आरोप बनाने के लिए तलब किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान वादी आकाश मिश्र कोर्ट में अपने अधिवक्ता के जरिये कोर्ट में हाजिर था। मगर, आरोपी डॉक्टर के अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्तूबर नियत कर दी। हार्निया से पीड़ित आकाश अपने साथी प्रसून के साथ 3 अप्रैल 2018 को बीएचयू अस्पताल के सर्जरी विभाग में दिखाये गया था। आरोप है कि डॉक्टरों की टीम ने अमानवीय व्यवहार करते हुए उस पर हमला कर दिया था। इससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी और टांके लगे थे। पहले पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया था। फिर, कोर्ट के आदेश पर बीएचयू के डॉक्टरों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक	देश की उपासना
स्वात्वाधिकारी में, प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।	
सम्पादक श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव	
मो० - 7007415808, 9628325542, 9415034002	
RNI NO - UPHN/2022/86937	
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com	
समाचार-पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।	

शिव की काशी में नवरात्रि की धूम

वाराणसी, संवाददाता। शिव की नगरी काशी शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा से शक्ति की आराधना में लीन हो जाएगी। हर-हर महादेव के जयघोष के साथ ही जय मां दुर्गे के जयकारे भी सुनाई देंगे। पहली बार श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में कलश स्थापना होगी और नौ दिनों तक सप्तशती के ओजस मंत्र से धाम गुंजायमान होगा। इसके साथ ही शहर के पांच स्थानों पर मां दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तीन से 11 अक्तूबर तक मां दुर्गा की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र मनाया जाएगा। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा तीन अक्तूबर से नवरात्र शुरू होगा। इस बार नवरात्र में चतुर्थी तिथि की बढोत्तरी और नवमी तिथि का क्षय है। इसलिए 11 अक्तूबर को ही महाष्टमी व महानवमी व्रत रखा जाएगा। तीन अक्तूबर को कलश स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:07 बजे से सुबह 9:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:37 बजे से 12:23 बजे तक रहेगा। हालांकि सुबह से शाम तक घट स्थापना कभी भी की जा सकती है। शास्त्रानुसार सुबह घट स्थापना का विशेष महत्व है।